

# जेन स्ट्रीट ने मूल्य हेरफेर मामले में सेबी के खिलाफ SAT का दरवाजा खटखटाया

फ़र्म ने एकीकृत निगरानी विभाग की पूरी रिपोर्ट और सेबी का एनएसई के साथ पत्राचार मांगा है; सैट की सुनवाई 8 सितंबर को

बिजनेसलाइन द्वारा समीक्षा किए गए दस्तावेजों के अनुसार, अमेरिका स्थित हाई-फ़्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फ़र्म जेन स्ट्रीट ग्रुप ने बाज़ार में हेरफेर के एक चल रहे मामले में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के खिलाफ़ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) का रुख़ किया है।

बुधवार को दायर की गई अपील में कहा गया है कि सेबी ने फ़र्म के बचाव के लिए "महत्वपूर्ण और प्रासंगिक दस्तावेजों" तक पहुँच देने से इनकार कर दिया है।

जेन स्ट्रीट ने सेबी के एकीकृत निगरानी विभाग (आईएसडी) की पूरी रिपोर्ट और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सेबी के बीच उसके कारोबार से संबंधित सभी पत्राचार सहित रिकॉर्ड की पूरी जाँच के निर्देश माँगे हैं।

जेन स्ट्रीट ने कहा कि सेबी ने अपनी जाँच टीम और एनएसई के पहले के निष्कर्षों को छोड़ दिया है, जिसमें कोई मूल्य हेरफेर नहीं पाया गया था। फ़र्म ने कहा कि आईएसडी द्वारा मामले को आगे न बढ़ाने के निष्कर्ष के बावजूद, नियामक ने बिना किसी स्पष्टीकरण के अपना रुख़ बदल दिया।

जेन स्ट्रीट ने अपनी अपील में आईएसडी के दिसंबर 2024 के निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा, "90% से ज़्यादा मामलों में, यह साबित नहीं हो सका कि जेन स्ट्रीट समूह की व्यापारिक गतिविधि उसके घटकों/सूचकांक के मूल्य में इस तरह से बदलाव के कारण हुई है जिससे डेरिवेटिव सेगमेंट में समूह के अन्य सदस्यों की खुली पोजीशन को फ़ायदा हुआ हो।"

इसके अलावा, जिन पाँच मामलों में सूचकांक की कीमतें उनके पक्ष में गईं, वहाँ लाभ नगण्य था। सैट ने मामले की सुनवाई 8 सितंबर के लिए सूचीबद्ध की है।

इस मामले पर स्पष्टीकरण के अनुरोध का न तो जेन स्ट्रीट और न ही सेबी ने कोई जवाब दिया।

(लेखक द हिंदू बिजनेसलाइन से जुड़े हैं)

## ‘इंट्राडे पोजीशन सीमा पर सेबी ढांचा हेरफेर को रोकेगा’

विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा किसी इकाई स्तर पर इंडेक्स इक्विटी डेरिवेटिव्स की इंट्राडे पोजीशन सीमा बढ़ाने के लिए अपनाए गए ढाँचे से निगरानी बढ़ेगी और हेरफेर मुश्किल होगा।

आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के संयुक्त सीईओ फ़िरोज अज़ीज ने कहा, "कम इंट्राडे कैप से व्यापारिक गतिविधियाँ बाधित होतीं और तरलता प्रभावित होती। चुनी गई सीमा बाजार निर्माताओं और संस्थागत खिलाड़ियों को सब कुछ स्पष्ट निगरानी वाली सीमाओं के भीतर रखते हुए काम करने की गुंजाइश देती है।"

शार्दूल अमरचंद मंगलदास के प्रतिभूति वकील और पार्टनर योगेश चंदे ने कहा, "इससे किसी बड़े खिलाड़ी के लिए बाजार में हेरफेर करने की संभावना अवरुद्ध हो जाती है और मूल्य निर्धारण को विकृत करना मुश्किल हो जाता है।"

नियामक ने वास्तविक समय में एकल संस्थाओं की पोजीशन सीमा की निगरानी करने का भी निर्णय लिया।

श्री चंदे ने कहा, "वास्तविक समय की निगरानी जोखिम की सटीक तस्वीर प्रदान करती है और विश्वास और भरोसा बनाने में मदद करती है, जिससे किसी भी दिन किसी विशेष समय पर बेहतर जोखिम के साथ बाजार अधिक निष्पक्ष बनता है।"

इसके अलावा, ओपन इंटरेस्ट के जोखिम की गणना एक नई डेल्टा-आधारित पद्धति के आधार पर की जाएगी, जो विकल्प अनुबंधों का अधिक जोखिम-भारित दृष्टिकोण है।

श्री चंदे ने कहा, "डेल्टा-आधारित दृष्टिकोण प्रत्येक स्थिति को उसके डेल्टा मान के आधार पर तौलता है, जिससे बाजार के वास्तविक आर्थिक जोखिम का पता चलता है। इसलिए, यह दृष्टिकोण इस वास्तविकता को स्वीकार करता है कि सभी अनुबंध समान नहीं होते हैं या उनमें समान जोखिम नहीं होते हैं। संशोधित दृष्टिकोण खुदरा निवेशकों की भी रक्षा करता है और मौजूदा ढाँचे के दुरुपयोग से बचाता है, क्योंकि यह इसमें शामिल जोखिम को अधिक सटीक रूप से समझता और कल्पना करता है।"

## INBRIEF



### नए ऑर्डरों में तीव्र वृद्धि से सेवा पीएमआई 15 वर्ष के उच्चतम स्तर पर

एक मासिक सर्वेक्षण में बुधवार को कहा गया कि मांग की स्थिति में पर्याप्त सुधार के बीच नए ऑर्डरों और उत्पादन में तेज वृद्धि के कारण सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर अगस्त में 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया कि पैनल के सदस्यों ने एशिया, यूरोप, मध्य पूर्व और अमेरिका में ग्राहकों की ओर से अधिक मांग का संकेत दिया। एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स जुलाई के 60.5 से बढ़कर अगस्त में 62.9 हो गया, जो जून 2010 के बाद से विस्तार की सबसे तेज दर को दर्शाता है।

### भारत, ईएफटीए व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से लागू होगा

स्विट्जरलैंड ने बुधवार को कहा कि भारत और चार यूरोपीय देशों के समूह ईएफटीए के बीच 1 अक्टूबर से लागू होने वाले मुक्त व्यापार समझौते में कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधान होंगे। उसने एक बयान में कहा, "पहली बार, भारत ने एक मुक्त व्यापार समझौते में व्यापार और सतत विकास पर कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधान निर्धारित किए हैं।" यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्य आइसलैंड, लिकटेन्स्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड हैं। पीटीआई

### सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र के मुद्दों का अध्ययन करने के लिए पैनल गठित किया

एक अधिकारी ने बताया कि सरकार ने विनिर्माण इकाइयों के सामने आ रही कर और निर्यात मंजूरी संबंधी समस्याओं की जाँच करने और अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च शुल्कों के बीच व्यवस्था को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति में वित्त मंत्रालय, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य विभाग, DGFT और RBI के प्रतिनिधि शामिल हैं।

## कैबिनेट ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए 1,500 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी

The Hindu Bureau  
NEW DELHI

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के पु्थक्करण और उत्पादन हेतु देश में पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करने

हेतु ₹1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी।

महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण में तांबा, लिथियम, निकल, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्वों जैसे जीवन-अंत उत्पादों से महत्वपूर्ण खनिजों की प्राप्ति शामिल है। यह

प्रोत्साहन राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) का हिस्सा होगा, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों में घरेलू क्षमता और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बनाना है।

वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक छह वर्षों की अवधि के लिए निर्धारित, ई-कचरा, लिथियम-आयन बैटरी (एलआईबी) स्क्रेप, और जीवन-अंत वाहनों में उत्प्रेरक

कनवर्टर के रूप में अन्य स्टॉक पात्र फीडस्टॉक के रूप में योग्य होंगे।

यह योजना कुल परिव्यय का एक-तिहाई छोटे और नए लाभार्थियों के लिए निर्धारित

करती है, हालाँकि लाभार्थियों में बड़े और स्थापित पुनर्चक्रक दोनों शामिल हो सकते हैं। सरकार ने निर्दिष्ट किया है कि पात्र संस्थाओं को नई इकाइयों में निवेश के साथ-साथ मौजूदा इकाइयों के विस्तार, आधुनिकीकरण या विविधीकरण के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।

## 📢 इस संदेश को फैलाने में हमारी मदद करें!

प्रिय छात्रों,

हिंदी माध्यम के छात्रों को अपडेट रहने और अपनी अंग्रेजी सुधारने में मदद करने के लिए हम द हिंदू अखबार का हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं।

🌐 **कृपया इस वेबसाइट** <https://epapers.netlify.app/> को अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ साझा करें ताकि अधिक छात्र लाभ उठा सकें।

🎯 **लक्ष्य:** जैसे ही 1,000 छात्र जुड़ेंगे, आपको हर दिन सुबह 6 बजे से पहले अखबार मिलना शुरू हो जाएगा!

आपका सहयोग देश भर के हजारों हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आइए, मिलकर इस शिक्षण समुदाय को आगे बढ़ाएँ!



धन्यवाद पढ़ते और सीखते रहिए!

CLICK HERE

